

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूंगरगढ
मुकदमा नम्बर 111/2018 निर्णय दिनांक 18.12.2019

स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा

बनाम

सहायक जनरल मैनेजर (प्लानिंग) जी.एम. टी.डी. पब्लिक पार्क वीकानेर जिला
वीकानेर

-----वादी

उपस्थिति-

-----प्रतिवादी

1. पैरोकार राज वादी की तरफ से
2. श्री अरुण मित्तल अधिवक्ता प्रतिवादी की तरफ से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

यह वाद इस न्यायालय में स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूंगरगढ ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रोही मोमासर तहसील श्री डूंगरगढ स्थित खसरा नम्बर 419 तादादी 0.25 हैक्टर प्रतिवादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रतिवादी ने बिना किसी सक्षम स्वीकृत व बिना भूमि का रूपान्तरण करवाये बीएसएनएल टावर का निर्माण कर लिया है जो कि काश्तकारी अधिनियम के खिलाफ है । प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बीएसएनएल टावर लगाया जाने के कारण कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है । इस प्रकार प्रतिवादी के विरुद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ कानूननी कार्यवाही करने के लिए वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रतिवादी को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.9.2016 को नोटिस जारी कर अवैध रूप से लगाये गये बीएसएनएल टावर को हटाने व कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाने हेतु बार बार लिखा गया लेकिन बाद गुजरने मियाद भी प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही नहीं की और ना ही अवैध टॉवर को हटाया है ना ही रूपान्तरण करवाया है । प्रतिवादी द्वारा किया गया उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्तों के उल्लंघन करने की तारीफ में आता है । जिसका खातेदार को किसी भी प्रकार से हक हासिल नहीं है और ना ही अधिकार प्राप्त है । खातेदारी अपनी खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार से नेचर परिवर्तन नहीं कर सकता है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मोमासर तहसील श्री डूंगरगढ में स्थित खातेदारी खेत खसरा नम्बर 419 तादादी 0.25 हैक्टर में से 234 वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के आदेश फरमावे तथा खातेदारी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने हेतु आदेश फरमावे अन्य कोई अनुतोष जो वादी के पक्ष में उचित हो फरमाई जावे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि भारत सरकार के पोस्ट एण्ड टेलीग्राम मैनुयूल द्वितीय की धारा 467 के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिवादी के विभाग की जमीन एवं भवन में किसी भी प्रकार की बाधा डालने से इंकार किया गया है । वादी का दावा विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है । वादी को विनायदावा प्राप्त नहीं हुआ है तथा विनाय दावा प्राप्त नहीं होने से दावा चलने योग्य नहीं है । भूमि संपरिवर्तन नियम जो धारा 92 ए भूराजस्व अधिनियम के तहत बने है के तहत एक बीघा भूमि की हद तक भूमि का किसम परिवर्तन कराना



उपखण्ड अधिकारी
डूंगरगढ (वीकानेर)

अनिवार्य नहीं है । प्रतिवादी की भूमि 0.25 हैक्टर है जो कि एक वीघा के अन्दर आती है । वादी अगर प्रतिवादी को भूमि परिवर्तन के लिए नोटिस देता है तो प्रतिवादी द्वारा वादी के नोटिस पर विचार किया जा सकता है । अतः जबाब पेश कर निवेदन किया है कि वादी का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।


बहस उभय पक्ष सुनी गई । पैरोकार राज ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थनी द्वारा कृषि भूमि पर बिना किसी सक्षम अनुमति के टावर स्थापित कर लिया है । अतः उक्त रकबा राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए खातेदार की टीनेन्सी समाप्त की जावे । प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि पोस्ट एण्ड टेलीग्राम मैनुयूल द्वितीय की धारा 467 के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिवादी के विभाग की जमीन एवं भवन में किसी भी प्रकार की बाधा डालने से इंकार किया है । इसके अलावा भूमि संपरिवर्तन नियम जो धारा 92 ए भूराजस्व अधिनियम के तहत बने है उसके तहत भी एक वीघा भूमि की हद तक भूमि का किस्म परिवर्तन कराना अनिवार्य नहीं है । अतः वादी वाद खारिज किया जावे ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी ने कृषि भूमि का बिना किसी सक्षम अनुमति के टावर का निर्माण किया गया है । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का स्पष्टतः उल्लंघन है । अतः वादी का वाद स्वीकार स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 419 तादादी 0.25 हैक्टर भूमि में से 234 वर्गमीटर भूमि वाके रोही मोमासर तहसील श्री डूंगरगढ जिसमें प्रतिवादी द्वारा टावर का निर्माण कर रखा है उस भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर प्राथी की उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है । तहसीलदार, श्री डूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें । निर्णय की पालना अपील मियाद गुजरने के बाद की जावे । डिक्री जारी हों ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । निर्णय इजलास सुनाया गया ।


(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ (जाकावर)



डिकी मुकदमें इन्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ

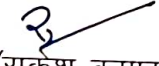
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल आरएएस..
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्री डूंगरगढ बनाम सहायक जनरल मैनेजर
(प्लानिंग) जीएमएण्ड टीडी बीकानेर
मुकदमा नम्बर 111/2018

निर्णय दिनांक 18.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत वहाजरी वादी की ओर से पैरोकार राज अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की तरफ से श्री अरुण कुमार मित्तल अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 419 तादादी 0.25 हैक्टयर भूमि में से 234 वर्गमीटर भूमि वाके रोही मोमासर तहसील श्री डूंगरगढ जिसमें प्रतिवादी द्वारा टावर का निर्माण कर रखा है उस भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर प्राथी की उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है । तहसीलदार, श्री डूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें ।

लीज.....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह
...0...फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयावी.....को अदा करें ।

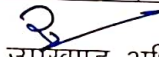
बसिब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 16 माह दिसम्बर सन् 2019 को जारी किया गया ।


(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ



वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0


उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ
श्री डूंगरगढ (बीकानेर)